

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं.1645

जिसका उत्तर 11.02.2021 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

1645. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में लंबित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में पूरी की गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) इन राज्यों में रोकी गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या कोविड-19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन से उक्त परियोजनाओं की प्रगति में बाधा आई है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख): दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में चल रही और पूरी हो चुकी राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा) परियोजनाओं का विवरण अनुबंध- I में क्रमशः तालिका I और तालिका II पर दिया गया है।

(ग): इन राज्यों में रूकी हुई राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा) परियोजनाओं के विलंब के कारण के साथ विवरण अनुबंध- II में दिया गया है।

(घ) और (ङ): जी, हां। देश में लॉकडाउन के कारण शुरू में परियोजनाओं की प्रगति बाधित हुई थी। तथापि, सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बावजूद निर्माण की उच्च दर बनाए रखने के लिए कई पहल की गई हैं। निर्माण की गति को बनाए रखने के लिए समय सीमा (3 से 6 माह) बढ़ाने, नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध प्रावधानों में छूट, उप-ठेकेदारों को सीधे भुगतान करने, ठेकेदारों के नकदी प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रतिधारण / प्रतिभूति राशि जारी करना, निष्पादन प्रतिभूति (नए अनुबंधों के लिए) प्रस्तुत करने में देरी के मामले में जुर्माने की छूट के जरिए आत्मनिर्भर भारत के तहत ठेकेदारों, रियायतग्राहियों और सड़क क्षेत्र के डेवलपर्स को हर संभव मदद देने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त, मजदूरों के प्रवासन को रोकने/ कम करने के लिए निर्माणस्थल के श्रमिकों को भोजन और चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई थी। सभी निष्पादन एजेंसियों / हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों, समन्वय और कार्यों की निगरानी के लिए अधिकतर संवाद डिजिटल तरीके से किया गया।

अनुबंध-I

‘राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं’ के संबंध में श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा पूछे गए दिनांक 11.02.2021 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 1645 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

तालिका I

(क) दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में चल रही रारा परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:-

लंबाई किमी में, लागत करोड़ रु. में				
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अदद	लंबाई	लागत
1	दिल्ली	6	50.30	9,388
2	हरियाणा	32	875.30	20,070
3	उत्तर प्रदेश	62	3,010.74	64,981
4	राजस्थान	69	3,474.51	37,512

तालिका II

(ख) दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में पिछले 3 वर्षों के दौरान पूरी हो चुकी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

लंबाई किमी में, लागत करोड़ रु. में				
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अदद	लंबाई	लागत
1	दिल्ली	1	8.72	1,237.24
2	हरियाणा	40	1,032.00	17,349.89
3	उत्तर प्रदेश	41	1,853.25	22,066.19
4	राजस्थान	102	3,036.24	15,879.10

अनुबंध-II

‘राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं’ के संबंध में श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा पूछे गए दिनांक 11.02.2021 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 1645 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(ग) विलंब के कारण के साथ रुकी हुई रारा परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्य का नाम	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रु. में)	एजेंसी	कारण
1	दिल्ली	शून्य				
1	हरियाणा	रारा 10 का दिल्ली/हरियाणा सीमा से रोहतक तक	63.49	486	एनएचएआई	वास्तविक प्रगति - 96.98% फगवाड़ा में 9.1 किमी की शेष लंबाई में से 2.75 किमी की परियोजना को स्टैंड-अलोन परियोजना के रूप में सौंपा गया है। रियायतग्राही द्वारा टोल संग्रहण को निलंबित कर दिया गया है और काम को जोखिम और लागत के तहत शुरू किया गया है
2		रारा 44 का पानीपत-जालंधर (छह लेन)	288.55	2748	एनएचएआई	वास्तविक प्रगति - 96.73% रियायतग्राही द्वारा टोल संग्रहण को निलंबित कर दिया गया है और काम को जोखिम और लागत के तहत शुरू किया गया है
3		दिल्ली और हरियाणा राज्यों में बीओटी (टोल) के आधार पर रारा -1 के 15.50 किलोमीटर पर मुकरबा चौक से 86.00 किमी पर पानीपत तक के खंड को 8-लेन का बनाना।	70.50	2129	एनएचएआई	वास्तविक प्रगति - 67.00 % एस्कॉ बैंकर के अनुरोध के अनुसार मूल रियायतग्राही मैसर्स एस्सेल को सौहार्दपूर्ण तरीके से प्रतिस्थापित कर दिया गया है और मैसर्स वेलस्पन ने प्राथमिकता पर शेष कार्य शुरू कर दिया है
1	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद-अलीगढ़	126.3	1026	एनएचएआई	एनएचएआई -मुख्यालय के सीसीआईई में डिस्कोप/सीओएस प्रस्ताव विचाराधीन है।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्य का नाम	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रु. में)	एजेंसी	कारण
2		बरेली सितारगंज	74.46	145	एनएचएआई	14/08/2020 को पीसीसी/पीसीओडी जारी की गई है। 250 मी. में पीजीसीआईएल द्वारा उपयोगी सुविधाओं के स्थानान्तरण का काम प्रभावित हुआ है।
3		बरेली सितापुर	157.59	697	एनएचएआई	सब्जेक्ट प्रोजेक्ट का शेष कार्य पहले ही सौंप दिया गया है और अब एनएचएआई द्वारा निर्धारित तारीख जारी की जानी है
1	राजस्थान	रारा-27 पर किमी 0.00 से किमी 10.300 (पैकेज I) तक उत्तरी कोटा बाइपास	10.30	98	पीडब्ल्यूडी	भूमि अधिग्रहण दरों के लिए जनता के विरोध के कारण पंचाट अधिनिर्णय के लिए लंबित मुकदमेबाजी का मुद्दा।
2		रारा 48 का गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खंड	225.60	3270	एनएचएआई	हरियाणा में वन भूमि, सिंचाई भूमि को सौंपने में अत्यधिक विलंब। रियायतग्राही के पास अपर्याप्त संसाधन और रियायतग्राही के समक्ष निधियों की कमी की समस्या।
